

कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का वर्तमान अध्ययन

हरगोविन्द खरेरा*

प्रस्तावना

लातीनी भाषा में कोरोना का अर्थ है मुकुट, जो गोल आकार में है एवं इस पर विभिन्न प्रकार की उभरी हुई काँटे जैसी आकृतियाँ होती हैं जैसे— सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है जिससे चंद्रमा के चारों ओर निकलने वाली जो किरणें दिखाई देती हैं। उस स्थिति को भी कोरोना कहते हैं। इस वायरस के कणों का व्यास लगभग 120 नैनो मीटर होता है, जो प्रोटीन से बना होता है और यह बिना किसी यंत्र के सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता है।

कोरोना वायरस अनेक प्रकार के विषाणुओं के वायरस का एक समूह है जो स्तनधारियों एवं पक्षियों में संक्रमित रोग उत्पन्न करता है जैसे—यह वायरस गाय और सूअर में अतिसार, मुर्गियों में ऊपरी श्वसन तन्त्र के रोग तथा मनुष्यों में श्वसन तन्त्र संक्रमण के रोग उत्पन्न करता है। यह वायरस सर्वप्रथम दिसम्बर 2019 में चीन के वुहान शहर में सामने आया तथा इसने तीव्रगति से पूरे वुहान शहर, चीन एवं पूरे विश्व में लोगों को अपने काल का ग्रास बनाया है। जिसके कारण इसने वैश्विक महामारी का विकराल रूप धारण कर लिया है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए विश्व में सभी देशों के वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य मशीनरी असफल हो गई थी लेकिन बड़े-बड़े देशों में वैज्ञानिकों ने अब इस वायरस को नियंत्रित करने के लिए कोविड वैक्सीन को तैयार करने में सफलता हांसिल की है। इस वायरस ने विश्व की महान आर्थिक शक्तियों वाले बड़े-बड़े देशों को भी लाचार कर था। कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व एवं भारत में अब तक क्रमशः 11,96,13,797 व 1,13,33,728 संक्रमित मामले सामने आए जिनमें से 9,62,57,884 व 1,09,73,260 व्यक्ति ठीक हुए तथा 26,51,728 व 1,58,483 व्यक्ति मृत्यु के ग्रास हो गए। डब्ल्यू.एच.ओ. ने इसको बतवदं टपतने क्पेमेंम 2019अर्थात्बटव.19का नाम दिया है। इस वायरस की उत्पत्ति के ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाए हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे चीन के वुहान शहर के मछली मार्केट में चमगाढा एवं सांप आदि में संक्रमण से तथा कुछ वैज्ञानिक इसे चीन के वुहान शहर के लैब में तैयार किया गया वायरस अर्थात् विभिन्न देशों में जैविक हथियार के रूप में उपयोग करने हेतु तैयार किया गया वायरस या जैविक हथियार मानते हैं। लेकिन चीन लगातार यह दावा करता आ रहा है कि यह वायरस किसी लैब से नहीं किया गया बल्कि मछली मार्केट से स्वतः उत्पन्न हुआ है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइड लाइन के अनुसार इस वायरस के संक्रमण के कारण 88:को बुखार, 68:को सूखी खाँसी और कफ, 38:को थकान, 18:को सांस लेने में तकलीफ, 14: को शरीर व सिर में दर्द, 11: को ठण्ड की शिकायत, 4:को डायरिया एवं रनिंग नोज/नाक बहना आदि लक्षण रोगी में दिखाई देने लगते हैं। बुखार में रोगी का तापमान 100 फारेनहाइट (37.7 सेलसियस) से अधिक हो जाता है।

* सहायक आचार्य ई.ए.एफ.एम., राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, अलवर एवं शोधार्थी राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान।

भारत में लॉकडाउन एवं कोरोना वायरस के प्रभाव

कोरोना वायरस से बचने एवं इसके फैलने से इसे रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन एवं विश्व में अनेक देशों की भाँति लॉकडाउन एवं सामाजिक दूरी ही एक मात्र उपाय था। इसलिए भारत में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया विधिवत रूप से दिनांक 24 मार्च 2020 के आदेशानुसार 24 मार्च 2020 रात्रि 12.00 बजे अर्थात् 25 मार्च 2020 से ही सम्पूर्ण भारत में प्रथम बार लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई। लॉकडाउन की प्रक्रिया के कारण भारत में नकारात्मक एवं सकारात्मक प्रभाव पड़े जो इस प्रकार हैं:

भारत में लॉकडाउन के नकारात्मक प्रभाव

- संयुक्त राष्ट्र की एक कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एण्ड डवलपमेन्ट (UNCTAD) के अनुसार भारत सहित विश्व की सबसे बड़ी 15 अर्थव्यवस्थाएँ कोरोना से प्रभावित हुई हैं।
- युरोप के आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आर्थिक विकास की गति 2020-21 में 1% से घट सकती है।
- नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा जारी अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कोरोना वायरस के कारण देश की जी.डी.पी. में 7.7% गिरावट होने की सम्भावना है जो कि वर्ष 1952 के निचले स्तर के नीचे भी जा सकती है। वित्त वर्ष 2019-20 में जी.डी.पी. 145.66 लाख करोड़ रुपये थी जो वर्ष 2020-21 में 134.50 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में 9% की गिरावट आने की सम्भावना है।
- इकनॉमिक्स विभाग, अन्तर्राष्ट्रीय संस्था आक्सफोर्ड ने अपनी नवीव ग्लोबल रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि वर्ष 2025 तक भारत की पर कैंपिटा जी.डी.पी. कोविड-19 के कारण 12% तक नीचे रहने की सम्भावना है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुसार कोरोना महामारी से वैश्विक स्तर पर पर्यटन उद्योग को वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले पाँच महिनों में 3200 करोड़ अमेरिकी डॉलर के निर्यात का नुकसान हुआ है। पूरे विश्व में भारत सहित 28 देशों की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग का लगभग 12% से 13% तक रहता है अर्थात् पर्यटन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ा है।
- भारत का सकल घरेलू उत्पाद 200 लाख करोड़ के लगभग हो जाता है। जिसमें 10% अर्थात् 20 लाख करोड़ का भारतीय पर्यटन में आकार है। जिस पर प्रत्यक्ष रूप से कोरोना वायरस का प्रभाव पड़ा है।
- वर्ल्ड बैंक की 29 देशों पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के बाद निम्न व निम्न मध्यम आय वर्ग वाले 65 देशों में शिक्षा के बजट में कटौती की तथा उच्च और उच्च मध्यम आय वर्ग वाले देशों में केवल 33% ने ही ऐसा किया है। भारत समेत अर्जेंटीना, ब्राजील, मिश्र, रूस, पाकिस्तान जैसे देशों में शिक्षा के बजट को 10% तक कम किया है।
- सितम्बर 2020 के अन्त में जारी संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार लॉक डाउन के दौरान अर्जेंटीना में 25%, साइप्रस और फ्रांस में 30%, सिंगापुर में 33% एवं पेरिस में 36% घरेलू हिंसा के मामले बढ़े हैं।
- राष्ट्रीय महिला आयोग के आंकड़ों के अनुसार देश में लॉक डाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 69, विवाहिताओं की प्रताड़ना के 15, दहेज हत्या के 2, बलात्कार के प्रयास के 13 मामले दर्ज किए गए। गरीमा के साथ नहीं जीने देने के 77 मामले बढ़े हैं।
- सोसाइटी ऑफ इण्डियन आटोमोबाइल मैनुफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार भारत के आटोमोबाइल उद्योग में आर्थिक मंदी आने के कारण लगभग 3.7 करोड़ कर्मचारियों के रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है।

- लॉकडाउन के कारण भारत में विभिन्न प्रकार की पार्टियों, शादियों एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगने एवं जनता में आर्थिक तंगी उत्पन्न होने के कारण घरेलू बाजार में मांग व विदेशी बाजारों में निर्यात होने के कारण हीरे जवाहरात व्यवसाय पर खतरा उत्पन्न हो गया।
- कोरोना के कारण 71: नौकरी पेशवरों के पास आगामी छः माह का खर्च, 15 लाख वार्षिक आय वर्ग वाले लोगों के पास 65: नकदी में गिरावट आई, 60: लोगों ने वित्तीय संकट के कारण यात्रारद्द की, 45: लोगों ने घर खरीदने के कार्य को बंद किया एवं 55: लोगों ने कार खरीदना स्थगित किया। इसी के साथ-साथ उद्योग क्षेत्र में 10.3%, सेवा क्षेत्र में 9.8%, माइनिंग क्षेत्र में 12.4%, उत्पादकता के क्षेत्र में 9.4%, निर्माणी क्षेत्र में 12.6%, शिक्षा के क्षेत्र में 10%, एवं रोजगार के क्षेत्र में 66%, की कमी आई है।
- लॉकडाउन के परिणामस्वरूप पूरे भारत में नर्सरी कक्षा से स्नातकोत्तर, पेशेवर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं कोचिंग संस्थान आदि को 25 मार्च 2020 से आगामी आदेश तक स्थगित किया हुआ था जिसे अब पुनः 18 जनवरी एवं 8 फरवरी 2021 50: उसस्थिति की संख्या के आधार पर चालू किया गया है। क्योंकि लॉकडाउन में सभी छात्र-छात्राओं को अपने घर पर ही रहने की हिदायत दी गई थी।
- लॉकडाउन के कारण कारखानों में अनुत्पादकता एवं लोगों में बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है।
- लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शब्द भाषण के अनुसार 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की रोजी-रोटी एवं घर वापसी की सबसे विकट समस्या उत्पन्न हो गई। क्योंकि दूसरे शहर में रोजगार नहीं, मकान मालिक द्वारा घर से निकालने पर रहने के लिए घर नहीं, पेट भरने के लिए भोजन नहीं, अपने घर वापस जाने के लिए किराया और यातायात के साधन नहीं जिससे कई करोड़ों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कुछ खाने को मिला तो ठीक नहीं तो भूखे ही अपने गन्तव्य स्थान पर चलते रहे। प्रवासी मजदूरों की पैदल यात्रा के दौरान कुछ श्रमिक गर्मी, रोड़ दुर्घटना, हार्ट अटैक, भूख, बस एवं ट्रेन दुर्घटना के शिकार हो गए। इस कहानी में इतना दर्द होता है कि आगे इसे बताना भी मुश्किल हो गया। क्योंकि यह लॉकडाउन नहीं श्रमिकों के जीवन डाउन का दौर था। क्योंकि लॉकडाउन की पैदल यात्रा में किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की मां, किसी की बहन एवं किसी का पूरा परिवार ही समाप्त हो गया और उन्हें कांधा देने के लिए भी कोई नहीं बचा।
- रिवर्स माइग्रेशन: रिवर्स माइग्रेशन मजदूरों को रहने, खाने एवं रोजगार देने की सरकार के सामने एक और समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में दोनों जगहं अर्थात् माइग्रेशन और रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में मजदूर मरने के लिए बजबूर हो गया।
- प्रजा फाउण्डेशन (श्रीराम इन्डुस्ट्रीयल स्टेट, बी-18, 13, जी.डी. अम्बेडकर मार्ग वडाला मुम्बई) के द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार 66: लोगों पर कोरोना का प्रत्यक्ष असर पड़ा है, 17: लोग पूर्णतः बेरोजगार हो गए हैं, 28: लोगों के वेतन में कटौती की गई, 25: लोगों ने बिना वेतन के भी कार्य किया, एवं 23: लोगों ने शहर छोड़ दिए और अपने गाँवों की ओर चले गए। दिसम्बर 2020 में प्रजा फाउण्डेशन ने 2087 परिवारों का सर्वेक्षण कर यह परिणाम निकाला है।
- लॉकडाउन के कारण कृषि एवं बागवानी फसल पूर्णतः नष्ट होने से कृषि एवं सहायक कार्यों से प्राप्त आय का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित हुआ था। क्योंकि फसल खेतों में तथा फल पेड़ों पर ही खराब हो गए जो कि मंडियों तक पहुंच ही नहीं सके। इसलिए किसान भुखमरी के शिकार होने लगे थे।
- देश में हर मध्यम आय वर्ग के नागरिक किसी न किसी प्रकार से ऋण लेकर अपने बड़े-बड़े कार्यों को पूरा करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते उनके सामने ऋण की किश्त चुकाने की समस्या उत्पन्न हो गई। ऐसे में मजदूर अपना पेट भरें या ऋण की किश्त भरें।

- मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े व्यवसाय जिस हालत में थे उसी हालत में ही बंद कर दिये गये और जिन्दा मुर्गियों को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया तथा उनके अंडों को नष्ट कर दिया गया ताकि यह वायरस इनके द्वारा न फैले।
- कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के चलते भारत में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें 25 से 30 रुपये तक बढ़ी हैं, जबकि विदेशों में क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 1.5 दशक के निचले स्तर पर ही रही हैं।
- लॉकडाउन में श्रमिक एवं कर्मचारी घर से निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनका कहना है कि घर से बाहर जाएंगे तो कोरोना वायरस के संक्रमण से मरेंगे, लेकिन घर से बाहर नहीं जाएंगे तो भूखे मरते हुए मरेंगे। ऐसे में भूखे मरने से अच्छा कमाते हुए ही मरेंगे तो कोई दुख नहीं होगा। यह व्यथा एक आम नागरिक की है लेकिन सरकार ने इन्हें कोरोना से मरने के लिए अपने स्तर पर ही छोड़ दिया है।
- कोराना के कारण हजारों की संख्या में कोरोना वीरों की मौते हो गई है।
- राजस्थान सरकार ने मार्च में तथा सितम्बर माह से आगामी आदेश तक कर्मचारियों के वेतन कटौती का भी आदेश जारी किया है।

भारत में लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव

- कोरोना वायरस महामारी की रोक-थाम हेतु विश्व में सभी देश अपने स्तर पर अपने-अपने लेब में कोरोना वैक्सीन तैयार करने में दिन-रात प्रयास कर रहे हैं इसके परिणामस्वरूप अमेरिका, रूस, चाइना एवं भारत आदि देशों ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार हेतु सफलता हांसिल की है।
- भारत में वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान में प्रथम फेज में पहली 16 जनवरी 2021 से प्रारम्भ की गई। खुराक लगभग 2 लाख कोरोना योद्धाओं को लगाने का लक्ष्य रखा गया। जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके के साथ देश में पहला कदम उठाया। प्रथम दिन 3352 स्वास्थ्य केन्द्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को प्रथम खुराक दी गई।
- देश में कोविड-19 की प्रथम खुराक में 77 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में कोविड-19 की दूसरी खुराक दिनांक 13 फरवरी 2021 से प्रारम्भ की गई। जिसमें वो व्यक्ति जिन्होंने प्रथम टीकाकरण कराया था तथा नए टीकाकरण भी प्रारम्भ किए गए हैं।
- विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट दिनांक 12 फरवरी 2021 के अनुसार भारत ने विश्व समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड वैक्सीन की कुल 229.7 लाख खुराक जिसमें 64.7 लाख खुराक अनुदान एवं 165 लाख खुराक की आपूर्ति वाणिज्यिक आधार विदेशों में की गई। जिन्हें किसी कारण टीकाकरण नहीं हो सका है उन्हें 6 मार्च 2021 से कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी।
- दवा उद्योग: कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण केवल दवाई उद्योग पर ही प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया, जबकि सरकार ने अस्पतालों एवं जनता में दवाईयों की पूर्ति बढ़ाने व इससे सम्बन्धित सेवाओं, संस्थानों, परिवहन के साधनों एवं कर्मचारियों को दवाई पूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित भी किया।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने भाषण दिया है कि व्यापारियों और उद्योगपतियों को कोविड-19 में राहत हेतु निर्धारित बिजली दरों में राहत देने के लिए योजना बनाई जा रही है।
- केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार ने मंत्रालयों और विभागों से गैर-जरूरी खर्च में कटौती करने के निर्देश दिए हैं।
- कोरोना संकटकाल में भी देश का विदेशी मुद्रा भण्डार 28 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.883 अरब डालर बढ़कर 543.431 अरब डालर पर आ गया जो अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया।

- भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राथमिकमा प्राप्त क्षेत्रों का ऋण श्रेणी दायरा बढ़ा दिया है। स्टार्ट-अप को भी बैंक ऋण की प्राथमिक श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके लिए स्टार्ट-अप क्षेत्र हेतु 50 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
- भारी एवं लोक उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 4 सितम्बर, 2020 को जारी किए गए भाषण में बताया कि वाहन उद्योग के लिए सरकार जल्द प्रोत्साहन की घोषणा करेगी। लेकिन वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) में 10% की कटौती की जा रही है।
- सरकार ने स्कूलों को एवं उनमें कार्यरत शिक्षकों को देश के सभी छात्र-छात्राओं को आनलाइन शिक्षा पद्धति से रेडियो, टी.वी., मोबाइल, लेपटाप एवं कम्प्यूटर के माध्यम से पढ़ाने, उनके टैस्ट व गृहकार्य कराने के लिए निर्देशित किया है।
- लॉकडाउन में सभी मजदूर, सरकारी एवं गैर-कर्मचारी सरकारी कर्मचारी अपने-अपने घरों में ही नियमित रूप से 3 से 6 माह तक परिवार के साथ रह रहे हैं। जिससे परिवार में बच्चे, वृद्ध, महिला व पुरुषों आदि में एक-दूसरे के प्रति स्नेह भावनाएँ, संस्कार और सामाजिक सेवाओं में विकास होने के कारण हर व्यक्ति अपने आप में खुश नजर आ रहा है।
- लॉकडाउन से प्रभावित श्रमिकों के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री ने यह घोषणा की कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के खाने के लिए अगले 2 माह तक 3500 करोड़ की राशि का ऐलान किया है। वित्त मंत्री के अनुसार राज्य सरकार से मिले आकड़ों के आधार पर देश में 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। जिन्हें यह सहायता दी जाएगी।
- प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अनेक निजी व्यक्तियों एवं संस्थाओं ने बस, ट्रक एवं रेल्वे के माध्यम से बिना किराए घर वापसी की है। जिससे मजदूर अपने घरों को वापस पहुंच सके हैं। इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखण्ड से पलायन करके दिल्ली एन.सी.आर., महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा पंजाब में सबसे अधिक मात्रा में पहुंच कर रोजगार प्राप्त करते हैं। रेल मंत्रालय की रिपोर्ट में रेल मार्ग से 10 लाख मजदूरों को घर वापस पहुंचाया है।
- लॉकडाउन के कारण पर्यावरण साफ हो गया। प्रकृति इतनी खुश हो रही है कि मानों प्रकृति यही चाहती है कि पृथ्वी को बचाने के लिए लॉकडाउन आवश्यक है। क्योंकि गंगा, यमुना एवं अन्य नदियों की सफाई के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए लेकिन गत 7 दशकों में भी इनकी सफाई नहीं हो पाई। लॉकडाउन के कारण सभी कारखाने बंद होने से वातावरण में कार्बन तथा विशैली गैसों तथा इन नदियों में गंदगी नहीं आई। जिससे ये सभी नदियाँ इतनी साफ हो गई कि गंगा नदी में निचली सहत पर गिरा हुआ 1 रुपये का सिक्का भी साफ दिखाई दे रहा है। देश की सरकारों ने इनकी सफाई के लिए कई अरबों रूपयों का खर्चा किया लेकिन गंदगी बरकरार रही। इसलिए कोरोना ने यह सिखा दिया कि कारखानों में से निकलने वाली गंदगी को नदियों की अपेक्षा किसी अन्य विकल्प में फेंकना पड़ेगा।
- कोरोना वायरस जैसी संकट की घड़ी में देश के 12 से अधिक बैंक आकस्मिक ऋण प्रदान करने के लिए तैयार हैं। ऐसे ऋण 6 माह तक चुकाने की जरूरत नहीं है और इस पर अगले 6 माह से 7% ब्याज दर पर ऋण चुकाया जा सकेगा। नौकरी पेशा के लोग अपनी अन्तिम सेलेरी का 20 गुणा अधिक अथवा अधिकतम 2 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं। जो 5 वर्ष में चुकता किया जा सकता है। लॉकडाउन से प्रभावित व्यापारियों को उनकी कार्यशील पूंजी का 10% तक ऋण दिया जाएगा। जिसके लिए ब्याज दर 8% होगी।
- विश्व बैंक ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत को 1 अरब डालर की मदद को मंजूरी दी है। इस राशि से भारत में कोरोना के प्रभावों को कम करने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी।

वित्तीय वर्ष 2021–21 के बजट में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभावों को कम करने के लिए निम्न प्रयास किए

- वर्ष 2021–22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कोरोना से बचने के लिये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु 2,23,846 करोड़ का स्वास्थ्य बजट का प्रावधान।
- बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन करके बीमा कम्पनियों में एफ.डी.आई. की सीमा 49: से बढ़ाकर 74: की जाएगी।
- बैंक ग्राहकों के लिए जमा बीमा की सीमा रु. 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की मंजूरी दी।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट की फण्डिंग को नया बैंक बनाया जाएगा।
- नए स्टार्टअप पर मार्च 2022 तक कर देयता समाप्त।
- 1.88 लाख करोड़ रुपये विनियम आय पर्यटन के क्षेत्र में हुई है जो पिछले साल से 7% अधिक है।
- आत्म निर्भर भारत के तहत 64000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना के प्रभाव कम करने हैं।
- पर्यटन के लिए 2026.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। जिससे पर्यटन रोजगार में वृद्धि होगी।
- कोरोना वायरस महामारी की रोक-थाम हेतु विश्व में सभी देश अपने स्तर पर अपने-अपने लेब में कोरोना वैक्सीन तैयार करने में दिन-रात प्रयास कर रहे हैं इसके परिणामस्वरूप अमेरिका, रूस, चाइना एवं भारत आदि देशों ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार हेतु सफलता हांसिल की है।
- भारत में वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान 16 जनवरी 2021 से प्रारम्भ किया गया। टीकाकरण अभियान के प्रथम फेज में पहली खुराक लगभग 2 लाख कोरोना योद्धाओं को लगाने का लक्ष्य रखा गया। जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके के साथ देश में ये पहला कदम उठाया गया। प्रथम दिन 3352 स्वास्थ्य केन्द्रों पर 1,91,181 स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को प्रथम खुराक दी गई। देश में कोविड-19 की प्रथम खुराक में 77 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। देश में कोविड-19 की दूसरी खुराक दिनांक 13 फरवरी 2021 से प्रारम्भ की गई। जिसमें वो व्यक्ति जिन्होंने प्रथम टीकाकरण कराया था तथा नए टीकाकरण भी प्रारम्भ किए गए हैं।
- 12 फरवरी 2021 को आई विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने विश्व समुदाय के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोविड वैक्सीन की कुल 229.7 लाख खुराक जिसमें 64.7 लाख खुराक अनुदान एवं 165 लाख खुराक की आपूर्ति वाणिज्यिक आधार विदेशों में की गई। जिन्हें किसी कारण टीकाकरण नहीं हो सका है उन्हें 6 मार्च 2021 से कोविड वैक्सीन की खुराक दी जाएगी।

सुझाव

- कोरोना वायरस बदलते समयानुसार अपनी स्थिति एवं प्रकृति परिवर्तित कर रहा है। इसी कारण विश्व में अभी तक किसी वैक्सीन की सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए जब तक वैज्ञानिकों द्वारा वैक्सीन का निर्माण करके जनसामान्य तक नहीं पहुंचाई जाए तब तक विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैज्ञानिकों एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की जाने वाली गाइडलाइन का सफलतापूर्वक ईमानदारी से पालन करने से ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है।
- कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन ने विश्व में प्रत्येक देश, उनकी सरकार, राजनीति, आर्थिक विकास के दावे, सामाजिक संस्कृति, सरकारी योजनाएँ, सरकार के विभिन्न बजटीय घोषणाओं में किए गए दावे आदि की पूरी तरह से पोल खोल दी है। इसलिए सभी को इस स्थिति से सबक लेना चाहिए।

- कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन ने इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, संस्था एवं सरकार सभी को कम खर्च में जीना सीखा दिया है अर्थात् अनावश्यक खर्च की अपेक्षा आवश्यक खर्च के सहारे आसानी से जीवन के सभी कार्य किये जा सकते हैं।
- कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन से पर्यावरण अथवा प्रकृति बहुत खुश है। पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, प्रकृति पर विनाश हेतु किए गए सभी कार्यों से प्रकृति पूरी दुखी हो गई थी, लेकिन अब मानों प्रकृति हमें यह संदेश दे रही है कि जब तक प्रकृति पर विनाशकारी अत्याचार होता रहेगा तब तक यह अपने बचाव के लिए ऐसी ही विनाशकारी महामारियां लाती रहेगी। अतः इससे पूरी दुनिया को सबक लेना चाहिए। (माल्थस का सिद्धान्तरूप जनसंख्या दोगुनी रफ्तार से बढ़ रही है तथा साधन सामान्य गति से बढ़ रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या 25 वर्ष बाद दोगुनी हो रही है इसलिए प्रकृति अपना संतुलन बनाए रखने के लिए समय-समय पर ऐसी महामारियाँ लाती रहती है।)
- भारत में कोरोना वायरस महामारी के कारण बाजार में आई आर्थिक मंदी के समाधान हेतु देश में विभिन्न आर्थिक विशेषज्ञों की एक राष्ट्रीय स्तर पर समिति बनाकर विश्व में अन्य देशों की भाँति आर्थिक विकास के नये मॉडल तैयार करने चाहिए।
- इस महामारी से पूर्व समाज में शादी और पार्टियों में दोनों पक्षों के द्वारा इतना अधिक खर्च किया जाता था कि मानों शादी नहीं बल्कि शादी के रूप में आन-बान-शान एवं धन शक्ति का दिखावा हो रहा हो, लेकिन इस लॉकडाउन में कम से कम खर्च एवं बिना दहेज के भी शादी का आयोजन होने लगा है।

निष्कर्षत

कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन की विकट स्थिति में देश के प्रत्येक व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी, व्यवसायी एवं सरकार को समय एवं परिस्थिति के अनुसार एवं सरकारी गाइड लाइन का सम्मान करते हुए संयम से अपने से सम्बन्धित हर किसी का आदर करते हुए अपनी कार्य योजना इस प्रकार निर्धारित करनी चाहिए कि किसी को भी हानि नहीं हो और देश में महामारी को समाप्त करते हुए आर्थिक विकास हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. रिजर्व बैंक बुलेटिन वीकली
2. रिजर्व बैंक सामयिक पत्र
3. रिजर्व बैंक वकिंग पेपर
4. इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली
5. आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20

सहायक पत्र-पत्रिकाएँ :-

1. जनसत्ता
2. टाइम्स ऑफ इंडिया
3. दैनिक भास्कर
4. दि इकोनॉमिक टाइम्स
5. हिन्दुस्तान
6. इंडिया टुडे
7. आउटलुक

